सम्पादक के नाम

राफेल सौदा, 'न खाऊंगा, न खाने दूँगा' कहनेवाले को 'खाऊँगा, खाने दूँगा' साबित कर रहा है

वित्तमंत्री जेटली ने बचाव की कोशिश की मगर फेल हो गए, रक्षामंत्री निर्मला सीतारमन ने कोशिश की, वह भी फेल हैं।शक गहराता जा रहा है।

1.सीतारमन कहती हैं कि वायुसेना के पास 36 से अधिक ऐसे विमानों को शामिल करने की क्षमता नहीं थी,इसलिए 126 नहीं, 36 विमानों का सौदा किया गया है।माना आपकी बात ठीक है तो यह बताएं कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में यह क्षमता 126 कैसे थी ?तब वायुसेना इतनी बड़ी संख्या में राफेल लड़ाकू विमान क्यों खरीदना चाहती थी ? ध्यान रहे आज तक मोदी सरकार ने एक बार भी उस समय के सौदे पर सवालिया निशान नहीं लगाए हैं, जबकि इस सरकार को अपना ही बचाव करना भारी पड़ रहा है।

2 यह सरकार कहती है कि हमने पिछली सरकार से कम कीमत पर सौदा किया है।अगर ऐसा है तो इस सरकार ने जितने में सौदा किया है, वह बता दे।अगर पिछली सरकार बता सकती थी तो यह सरकार क्यों नहीं ?अगर उसने गोपनीयता की शर्तों में कीमत को नहीं रखा था,तो इसने क्यों रखा है ? कीमत बताएंगे नहीं,सौदा सस्ते में किया है,यह बताएंगे।बताइए कोई कैसे विश्वास करे ? इसका पुख्ता, सप्रमाण भरोसा दिलाएँ तो मान भी सकते हैं।इसके लिए दोनों भारतीय सरकारों द्ववारा किए समझौते के दस्तावेज के अगोपनीय अंश सार्वजनिक किए जाएँ। इससे आपका यह दावा भी पुष्ट हो जाएगा कि PA सरकार का यह दावा गलत है कि वह जो कीमत बता रही है,वह सिर्फ बेसिक विमान की कीमत है, भारत की आवश्यकता के अनुसार जो विमान चाहिए, उसके लिए सज्जित विमान की नहीं। पिछली सरकार कह रही है कि हमने इसी कीमत में सुसज्जित विमानों का सौदा किया था।जब खाना नहीं है, खाने नहीं देना है तो यह दुराव क्यों नहीं ?

3.पिछली सरकार के समय इस सौदे में सरकारी क्षेत्र की प्रतिष्ठित और अनुभवी HAL को शामिल किया गया था। अगर सौदे से दो दिन पहले तक इसमें उसका नाम था तो समझौते के दिन हट क्यों गया ? अगर डसाल्ट का आग्रह ऐसा था तो क्या यह काम सरकार का नहीं कि जोर देती कि यह काम HAL से ही करवाया जाए,एक अनुभवहीन कंपनी से नहीं वरना भारत सरकार सौदा नहीं करेगी ? अगर सरकार देशहित में सरकारी कंपनी के लिए भी दबाव नहीं डाल सकती और एक निजी कंपनी (जिसकी क्षमता के बारे में आज इतने सवाल उठ रहे हैं) शामिल होने देती है ,तो वह किस तर्क से देशभक्त सरकार है ? और देशभक्त नहीं है तो किसकी भक्त सरकार है ?क्या वह पार्टी और सरकार देशभक्त होने का अपना दावा खुशी-खुशी वापिस लेगी ?

- विष्णु नागर

सोचें हम किस तरफ बढ़ रहे हैं

एक चौंकाने वाली बात हुई। हम तीन लोग अपने दफ्तर के थोड़ा पास में एक फास्टफूड कॉर्नर पर खड़े थे।

मैं सौ रुपये के नये नोट को देखकर मोदी की नोटबंदी के बारे में कुछ बोल रहा था।

तभी एक मजबूत कठकादी का आदमी आता है और पूछता है-

क्या हुआ मोदी जी का ?

क्या बात कर रहे हो ? मोदी जी क्या कर दिये ?

मैंने कहा कुछ भी तो ठीक नहीं किये। नोटबंदी से लेकर डिजल-पेट्रोल तक।

इतने में वो आदमी जोर-जोर से मेरे कंधे पर तीन-चार धौल जमाता है। जबतक मैं और मेरे दोस्त उससे पूछते हैं तबतक वो कुछ तीन-चार दिन में बतायेंगे, 2019 में पता चलेगा जैसा कुछ बोलते हुए वहां से तेजी से निकल गया। हमने उसे रोकने की कोशिश की। पीछे से आवाज भी लगाया। लेकिन तब तक वो जा चुका था। ये सब बमुश्किल 30 सेकेंड के भीतर घटी घटना है।

जबतक मुझे समझ आता कि एक तरह से उस आदमी ने मुझ पर जोर-जोर से मारा है, तबतक वो जा चुका था। पन्द्रह मिनट से शॉक्ड हूं। क्या सरकार की आलोचना करने वालों को इस तरह से डराने-धमकाने के लिये हर गली-मुहल्ले में गुंडे तैयार किये जा रहे हैं ?

आखिर वो कौन है जो नफरत के बीज हमारे बीच बो रहा है ?

मैं तो बिहार से आता हूं। हमारे यहां तो चाय दुकान से लेकर ट्रेन के डब्बे तक ऐसी राजनीतिक बहस बहुत आम बात है। सरकार की आलोचना, लोगों की मुश्किलों पर बातचीत सबकुछ बचपन से करता आया हूं, सुनता रहा हूं। चाहे वो कॉन्ग्रेस का जमाना हो या फिर लालू और नीतीश का।

अब आखिर क्या मोदी सरकार की आलोचना करने वालों का क्या सच में मॉब लिंचिंग किया जायेगा ?

पता नहीं, हो सकता है मैं सदमे में हूं, मैं हो सकता है इस छोटी सी घटना के बाद पैनिक हो रहा हूं।

लेकिन पता नहीं अचानक से डर तो लगा ही है। देशभर में जिस तरह मॉब लिचिंग और आये दिन लोगों के साथ मारपीट की घटना की खबरें आ रही हैं उसका असर तो है ही।

मैं तो फिर भी सोशली एक प्रिविलेज लोकेशन से आता हूं। मेरी मॉब लिचिंग की संभावना सबसे आखिरी में होगी। लेकिन जो लोग शोषित और मॉइनरिटी कम्यूनिटी से आते हैं, उनके लिये सोचिये...

उनके लिये हमने कैसा असुरक्षित समाज बना दिया है ?

मेरे कई दोस्त बताते रहे हैं कि ट्रेन में, चाय दुकानों पर या कही भी सार्वजनिक रूप से मोदी सरकार की आलोचना तो जाने दीजिए सामान्य राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी बात करने में डर लगने लगा है। आज उनके उस डर को थोड़ा और करीब से देख पा रहा हूं।

थोड़ा सा असहज हूं फिलहाल। पता नहीं, मोदी समर्थक इस बात की गंभीरता को कितना समझ रहे हैं लेकिन एक ऐसा देश जहां असहमति की छोटी से छोटी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, वो न तो देश के लिये अच्छा है और न ही बेहतर समाज के लिये। और अगर किसी को लग रहा है कि चुप रहकर सुरक्षित है तो वो बहुत भ्रम में है। एक दिन ये हिंसक भीड़ आपके कंधे पर भी हाथ रखेगी और आपके घरो के दरवाजे भी खटखटायेगी।

-अविनाश चंचल

खबर (दार) झरोखा

गिरीश मालवीय

वित्तमंत्री अरुण जेटली को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए!

विजय माल्या ने जो लंदन आने से पहले अरुण जेटली से हुई मुलाकात के बारे में कहा है वह अब एक ओपन ट्रूथ है। बहुत से लोगो को लगता है कि माल्या के मुद्दे पर राहुल गाँधी जो जेटली के इस्तीफे की मांग कर रहे है वह सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ऐसा कर रहे हैं लेकिन सच्चाई तो यह है कि माल्या ने कल वही बात बोली है जो कांग्रेस प्रवक्ताओ ने 2016 में माल्या के लंदन भागने के ठीक बाद में बोली थी।

उस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर गंभीर प्रश्न उठाते हुए कहा था कि 2 मार्च 2016 को माल्या के लंदन जाने से ठीक एक दिन पहले 1 मार्च 2016 को माल्या ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और वित्त मंत्रालय के कुछ अफसरों से मुलाकात की थी, उसके बाद वे विदेश भाग गए, क्या जेटली ने इस मुलाकात के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को बताया ? मुलाकात में क्या बातें हुईं ? क्या जेटली मुलाकात का ब्यौरा संसद को देंगे ?

अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए जिसे इस देश का गोदी मीडिया आज दबा कर बैठा हुआ है और हिम्मत नही कर पा रहा कि मोदी सरकार से पूछ ले कि आखिर माल्या के खिलाफ जो मूल लुकआउट नोटिस जारी किए गए थे उसे वापस क्यों लिया गया ? और लुकआउट नोटिस के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए आप खुद सोचिए कि माल्या आज यह कहता है कि मैंने लंदन जाने से पहले जेटली को यह बताया था कि 'मैं लंदन जा रहूं हूँ' तो इस बात का क्या मतलब है ? दरअसल विजय माल्या के खिलाफ सीबीआई ने जुलाई 2015 में खुद ही आईडीबीआई बैंक लोन मामले में भ्रष्टाचार और आपराधिक षडयंत्र की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। 2 मार्च 2016 की तारीख में सीबीआई को पता था कि विजय माल्या लंदन जा रहे हैं। यहाँ तक कि एयरपोर्ट से इमिग्रेशन ने सीबीआई को बताया भी था कि माल्या जा रहे हैं लेकिन सीबीआई ने माल्या के जाने पर कोई आपत्ति नही ली तो आप अंदाजा लगाइये कि ऐसा किसके आदेश पर कहा गया होगा ?

सच्चाई यह है कि सीबीआई ने अक्टूबर 2015 में माल्या के नाम लुकआउट नोटिस यानी देश से जाते समय पकड़ लेने का नोटिस जारी किया था लेकिन एक महीने बाद नंवबर में वो नोटिस वापस ले लिया था और लुक आउट नोटिस में बदलाव कर कहा गया कि अगर विजय माल्या देश से बाहर जाने की कोशिश करें तो सीबीआई को जानकारी दी जाए और ये भी बताया जाए कि वो कहां गए हैं। इसी आधार पर सीबीआई को 2 मार्च को ये पता चला था लेकिन सीबीआई ने कहा.....'जाने दो'।

लुकआउट नोटिस में ऐसा चेंज किसके इशारे पर किया गया समझना मुश्किल नही है। इस बात के भी बहुत से सुबूत मिल जाएंगे कि माल्या के संबंध जेटली से बड़े घनिष्ठ थे।

जब माल्या लंदन में थे तो उन्होंने एक पत्र मोदी और जेटली को लिखा था और वह पत्र ट्विटर पर साझा भी किया था। माल्या लिखते हैं 'मैंने 15 अप्रैल 2016 को पीएम मोदी और वित्त मंत्री जेटली को पत्र लिखा था। इस चिट्ठी को सार्वजनिक कर रहा हूं ताकि चीजें सही परिपेक्ष्य में आ सकें। मोदी और जेटली दोनों में से किसी का भी इस पत्र का जवाब नहीं आया।'

ये तो हुई अरूण जेटली के साफ साफ दिख रही इन्वॉल्वमेंट की बात, अब आप यह समझिए कि माल्या के केस में मोदी सरकार कितनी गंभीर है और कितनी तत्परता से कार्यवाही कर रही है.....

भगोड़े माल्या को लंदन में रहते ढाई साल होने वाले हैं लेकिन वित्त मंत्रालय को अब तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि किंगफिशर के मालिक विजय माल्या ने कितना लोन लिया है ?

सेंट्रल इंफॉरमेशन कमिशन यानी सीआईसी को दिए एक जवाब में मंत्रालय ने कहा है कि उसके पास माल्या का कोई लोन रिकॉर्ड नहीं है। वित्त मंत्रालय की यह दलील मोदी सरकार के पारदर्शिता के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है।

यह जानना भी आपके लिए आल्हादकारी अनुभव साबित होगा कि वास्तविक रूप में माल्या की संपत्ति की नीलामी से कितनी रकम सरकार को प्राप्त हुई है। 21 मार्च को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने संसद को बताया था कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक की जानकारी के मुताबिक माल्या की संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी से अभी तक सिर्फ 155 करोड़ रुपये ही हासिल हो पाए हैं।

और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मोदी सरकार बेनामी संपत्तियों के मामलों के निपटाने के लिए नया कानून बनाने के डेढ़ साल बाद अभी इन मामलों की सुनवाई के लिए जरूरी जुडिशल अथॉरिटी का गठन ही नहीं कर पाई जबकि संबित पात्रा सरीखे जोकर नुमा प्रवक्ता टीवी पर ताल ठोकते हुए पाए जाते हैं कि नए कानून के तहत माल्या सरीखे डिफाल्टर की बेनामी संपत्ति मोदी सरकार तेजी से जब्त कर रही है। हकीकत यह हैं कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के लागू होने के बाद कुर्क हुईं 860 संपत्तियों में 780 के मामले अभी तक लंबित हैं।

सच तो यह है कि मोदी जी ओर जेटली के खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और।

बोलिए मोदी जी, देश को बोलने वाला नेता चाहिए था..बोलिए न...

विपिन जैन

भाषणों के मास्टर कहे जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2013 के साल में जब वे डॉलर के मुक़ाबले भारतीय रुपये के गिरने पर दहाड़ रहे थे तब लोग कहते थे कि वाह मोदी जी वाह। ये हुआ भाषण। ये भाषण नहीं देश का राशन है। हमें बोलने वाला नेता चाहिए। पेट को भोजन नहीं भाषण चाहिए। यह बात भी उन तक पहुंची ही होगी कि पब्लिक में बोलने वाले नेता का डिमांड है। बस उन्होंने भी बोलने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पेट्रोल महंगा होता था, मोदी जी बोलते थे। रुपया गिरता था, मोदी जी बोलते थे। ट्विट पर रि-ट्विट। डिबेट पर डिबेट। 2018 में हम इस मोड़ पर पहुंचे हैं जहां 2013 का साल राष्ट्रीय फ्राड का साल नज़र आता है। जहां सब एक दूसरे से फ्राड कर रहे थे।

2014 आया। अख़बारों में मोदी जी की प्रशस्ति लिखना काम हो गया। जो प्रशस्ति नहीं लिखा, उसका लिखने का काम बंद हो गया। दो दो एंकरों की नौकरी ले ली गई। कुछ संपादक किनारे कर दिए गए। मीडिया को खत्म कर दिया गया। गोदी मीडिया के दौर में मैदान साफ है मगर प्रधानमंत्री पेट्रोल से लेकर रुपये पर बोल नहीं रहे हैं। नोटबंदी पर बोल नहीं रहे हैं। अभी तो मौका है। पहले से भी ज़्यादा कुछ भी बोलने का। नौजवानों को नौकरी ही तो नहीं मिली, भाषण तो मिल ही सकता है। विश्व गुरु का मीडिया भांड हो गया। बेहया हो गया। मीडिया कमज़ोर किया गया ताकि जनता को कमज़ोर किया जा सके। जब एंकर को हटाया जा सकता है तो सवाल पूछने वाली जनता तो दो लाठी में साल भर चुप रहेगी। यही भारत चाहिए था न, यही भारत है ,यहां आपकी आंखों के सामने।

क्या प्रधानमंत्री 2013 के अपने भाषणों से परेशान हैं ? या फिर 2019 के लिए उससे भी अच्छा भाषण लिखने में लगे हैं ? प्रधानमंत्री तब तक इतना तो कर सकते हैं कि पुराने भाषणों को ही ट्विट कर दें। बोल दें कि जो तब बोला था, वही आज सही है। बार-बार क्या बोलना। आप यह मान कर सुन लें कि यह 2018 नहीं 2013 है। महानायक बार-बार नहीं बोला करते हैं। वे तभी बोलते हैं जब उन्हें सुनाना होता है। तब नहीं बोलते हैं जब उन्हें जवाब देना होता है।

क्या उनका बोला हुआ भाषण उन्हें सता रहा है ? कई बार ऐसा होता है। श्री श्री रविशंकर तो एक डॉलर 40 रुपये का करवा रहे थे। पता नहीं वे अपने शिष्यों चेलों का सामना कैसे करते होंगे। रामदेव तो युवाओं को 35 रुपये लीटर पेट्रोल दिलवा रहे थे। अब वे भी चुप हैं। उनका विश्व गुरु भारत चुप है। इसी बुज़दिल इंडिया के लिए रामदेव युवाओं को 35 रुपये लीटर पेट्रोल भरवा रहे थे। अब 90 रुपये प्रति लीटर पर किसी को कोई तकलीफ नहीं है। प्रधानमंत्री को क्या क्या अचानक याद आ जाता होगा। अचानक याद आ जाता होगा कि अरे गुजरात चुनाव में साबरमती में पानी में उतरने वाला जहाज़ उतारा था, वो दोबारा क्यों नहीं उतरा। कोई पूछ तो नहीं रहा है। चिकोटी काटने लगते होंगे। यार ज़रा पता करो ,पूछने वाले सारे एंकर हटा दिए गए न। कोई बचा है तो उसे भी निकलवा दो। करोड़ों बेरोज़गार हैं इस देश में। नौकरी दे नहीं सका तो क्या हुआ, नौकरी ले तो सकता ही हूं। बाकी आई टी सेल सपोर्ट में तर्क तैयार कर दे। इन्हें अर्बन नक्सल बनवा दो।

सरकार में हर कोई दूसरा टॉपिक खोजने में लगा है जिस पर बोल सकें ताकि रुपये और पेट्रोल पर बोलने की नौबत न आए। जनता भी चुप है। यह चुप्पी डरी हुई जनता का प्रमाण है। इसलिए और भी ख़तरनाक है। वो कमेंट बॉक्स में लिखने लायक नहीं रही। इन बॉक्स में लिख रही है कि हमारी कमाई पेट्रोल पंप पर उड़ रही है। क्या जनता को भी नहीं दिखाई दे रहा है कि पेट्रोल 90 के पार चला गया है? डॉलर 73 के पार चला गया है।

जब इन्हीं सवालों पर 2013 में प्रधानमंत्री से पूछा जाता था तब 2018 में क्यों नहीं पूछा जा रहा है। ऐसा क्या हो गया है कि प्रधानमंत्री रुपये की ऐतिहासिक गिरावट पर बोल नहीं पा रहे हैं। राफेल डील पर बोल नहीं पा रहे हैं। रक्षा मंत्री बोलने वाली थीं, मगर उन्हें चुप करा दिया गया। वित्त मंत्री ब्लॉग लिख रहे हैं। पता चला कि रॉफेल पोस्टल विभाग में शामिल हो गया और रविशंकर प्रसाद उस पर डाक टिकट लगा रहे हैं।

डर। डर का सामाजिकरण हुआ है। यह प्रक्रिया पूरी हो गई है। डर ही है कि कहीं कोई सवाल नहीं है। जवाब के बदले डर है। आयकर का दारोगा, थाने का दारोगा आपके घरों में घुस जाएगा। टीवी पर नक्सल नक्सल चल जाएगा। इसलिए सब चुप है। क्या सबको चुप रहने के लिए, डरे हुए रहने के लिए बोलने वाला नेता चाहिए था? फिर बोलने वाले नेता को किस बात का डर है। क्या उन्हें भी अब बोलने से डर लगता है? होता है। कई बार डराते डराते डर खुद के भीतर भी बैठ जाता है। जो डरता है, वही डराता है। जो डराता है, वही डरता है।

ये बुज़दिल इंडिया है। जहां सवाल बंद है। जहां जवाब बंद है। टीवी पर जनवरी से 2019 में मोदी के सामने कौन का प्रोपेगैंडा चल रहा है। जनता के 2018 के सवाल ग़ायब कर दिए गए हैं। जनता भी ग़ायब हो चुकी है। वह भक्त बन गई है या समर्थक बन गई है या पता नहीं क्या बन गई है। जिस भारत में नौकरियां नहीं हैं. लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है उस भारत में 90 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल ख़रीदने की क्षमता कहां से आ गई है। क्या जनता अब उस हिन्दू मुस्लिम खांचे से बाहर नहीं आ पा रही है, क्या उसे बाहर आने से डर लग रहा है ?

बिजनेस स्टैंडर्ड में महेश व्यास ने भांडा फोड़ दिया है। इस साल की पहली तिमाही में जीडीपी 8.2 प्रतिशत हो गई। सरकार गदगद हो गई। लेकिन क्या आपको पता है कि रोजगार कितना बढ़ा है ?, इसी दौरान रोज़गार में 1 प्रतिशत की कमी आई है। तिमाही की जीडीपी संगठित क्षेत्रों के प्रदर्शन पर आधारित होती है। महेश व्यास का कहना है कि दूसरी तिमाही में भी रोज़गार में तेज़ी से गिरावट आई है। जुलाई 2017 से जुलाई 2018 के बीच काम करने वाले लोगों की संख्या में 1.4 प्रतिशत की गिरावट आ गई है। अगस्त में 1.2 प्रतिशत की गिरावट है। नवंबर 2017 से ही रोज़गार में गिरावट आती जा रही है। जबकि लेबर फोर्स बढ़ती जा रही है। यानी काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपलब्ध होते जा रहे हैं। नोटबंदी के बाद लेबर फोर्स सिकुड़ गया था। लोगों को काम मिलने की उम्मीद ही नहीं रही थी इसलिए वे लेबर मार्केट से चले गए। अब फिर से बेरोज़गार लेबर मार्केट में लौट रहे हैं। मगर काम नहीं मिल रहा है।

फिर रोज़गार पर कोई सवाल नहीं है। नौजवान अपना अपना बैनर लिए प्रदर्शन कर रहा है। कहीं कोई सुनवाई नहीं है। जब तक वह हिन्दू मुस्लिम कर रहा था, तब तक वह अपना था, जैसे ही नौकरी मांगने लगा, पराया हो गया। जैसे राजनीति उसे दंगाई बनाना चाहती हो, काम नहीं देना चाहती है। कुतर्कों की बाढ़ आई है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। ठाठ से कहते हैं कि ज़रूरत पड़ी तो वे नोटबंदी फिर करेंगे। अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की ऐसी हेकड़ी कभी नहीं सुनी। इसी नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी हैं। क्या यह उनका भी मत है ? जयन्त सिन्हा कहते हैं कि हवाई जहाज़ का किराया ऑटो से सस्ता हो गया है। क्या सही में ऐसा हुआ है ?

कोई कुछ भी बोल देता है मगर सवाल का जवाब नहीं देता है। कुछ भी बोल देता है ताकि बहस होने लगे। ताकि मुद्दे से ध्यान हट जाए। ताकि आप यह न पूछें कि रुपया ऐतिहासिक रूप से नीचे क्यों हैं। पेट्रोल के दाम 90 रुपये प्रति लीटर से अधिक क्यों हैं?